आंतरराष्ट्रीय बहुभाषिक शोध पत्रिका

प्रिंटिंग एरिया

Printing Area International Interdisciplinary Research Journal in Marathi, Hindi & English Languages

December 2017, Special Issue

श्री बालाजी संस्थान देऊळगाव राजा द्वारा संचालित

श्री व्यंकटेश कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय

देऊळगाव राजा, जि. बुलडाणा. पिन-४४३ २०४.

नॅक पुनर्मूल्यांकन 'ब ++' दर्जा प्राप्त

भारतीय कृषीक्षेत्रासमोरील आव्हाने व संधी

विशेषांक

मुख्य संपादक

प्रा. ज्ञानेश्वर विष्णू गोरे

प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग,

श्री व्यंकटेश कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय,

देऊळगाव राजा, जि. बुलडाणा.

ई-मेल : dvgore12@gmail.com, मोबाईल: ९१७५७२०३७५

डिसेंबर २०१७

Reg.No.U22120MH2013PTC251205

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.

At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed

Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295

harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com

All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

14)The Need of Kisan Credit Card in India for "Agricultural Finance ...
Yogesh K. Athave, Dist. Buldana (MS) || 49

15)प्रधानमंत्री कृषि सिचांई योजना
प्रा.डॉ. निता नन्दलाल तिवारी, अकोला || 51

16)भारतीय कृषि में पूंजी निर्माण (Capital Formation in Indian Agriculture)
Dr. Ganesh B. Darade & Mr. Ananta J. Pawar, Dist. Buldana (MS). || 55

17)शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि शासकीय पॅकेज वरवरची मलमपट्टी
प्रा. डॉ. संतोष तु. कुटे जि. बुलडाणा. || 57

18)मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या : एक अभ्यास
प्रा. डॉ. ए. बी. वायकर जि.जालना || 61

19)डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींचा मागोवा
डॉ. करमसिंग राजपूत,जि.यवतमाळ. || 64

20)भारतीय शेती क्षेत्रासमोरील आव्हान : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
प्रा. शिवाजी काकडे, जि. बीड || 67

21)शेतीच्या विकसात ठिबक सिंचन पध्दतीचे योगदान एक अभ्यास
डॉ.दयाळू किसन राठोड जि. अकोला. || 70

22)भारतीय शेती स्वरूप आणि आव्हाने
प्रा. डॉ. ि. जे. एस. सवाईथूल महा. अम. || 74

23)शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या – एक विश्लेषण
प्रा. डॉ. किशन सत्ताजी बाभुळगावकर वसमत || 77

24)भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषीविपननाचे महत्व
डॉ. केशव सुर्यभान गुल्हाने,जि. बुलढाणा || 80

25)भारतीय अर्थव्यवस्थेत साखर उद्योगाची भूमिका
डॉ. दिलीप का. खुपसे, जि. यवतमाळ || 83

26)शेतकरी आत्महत्या व ग्लेबल वार्मिंग
डॉ. एस.टी.वराडे, खामगांव || 85

https://sites.google.com/site/vidyawartajournal_http://www.vidyawarta.blogspot.com

कृषि वानिकी, चारा, सब्जियों और पुष्प
लए उप–नगरीय गंदे जल से सिंचाई को

सिक्किम के धर्म विकास कार्यक्रम का
करते हुए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू
र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे पर्वतीय
नों के जीर्णोद्धार पर विशेष बल देना।

परंपरागत पर्वतीय जल प्रबंधन प्रणालियों
न पध्दतियों जैसे बहूउद्देश्यीय जल उपयोग
जिनमें जल का इस्तेमाल घरेलू और लघु
के लिए संयुक्त रूप से होता है, उच्च–वर्षा
में जल्लौद प्रणाली, बांस ड्रिप प्रणाली,
गी और देशी ज्ञान आधारित अन्य पध्दतियों
करने में मदद करना।

महिलाओं और बालिकाओं पर विशेष
जो परंपरागत रूप से जल उपलब्ध कराने
मेदार होती हैं, सभी कार्यक्रमों मे सामुदायिक
र सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना।

पहले से जारी कार्यक्रमों जैसे मनरेगा,
सिंचाई मिशन के साथ समाभिरूपता और
यम करना।

:—

रूक्षेत्र ग्रामीण विकास को समर्पित, मासिक
नवम्बर २०१७.

www.deepawali.co.in

ttps:/www.mapsofindia.co.in

र्थसंवाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था विशेषांक
—जून २०१५.

जना मासिक २०११, जनवरी, चौराहे

16

भारतीय कृषि में पूंजी निर्माण (Capital Formation in Indian Agriculture)

Dr. Ganesh B. Darade,
Assistant Professor & Head,
Department of Economics,
Sant Bhagwan Baba Arts College, S. Raja, Dist. Buldana (MS).

Mr. Ananta J. Pawar,
Assistant Professor & Head,
Department of Economics,
Late N. J. Deshmukh Sr. College, Amdapur,
Dist. Buldana (MS).

****

भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में कृषि प्रमुख क्षेत्र होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होता है। अत: कृषि-उत्पादन में परिवर्तन (चाहे ये नवीन निवेश के कारण हों या तकनीकी परिवर्तनों अथवा मौसम में परिवर्तनों के कारण) कुल राष्ट्रीय आय को प्रभावित करते हैं और परिणामस्वरूप बचत तथा निवेश दरें भी प्रभावित होती हैं। संक्षेप में ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में कृषि क्षेत्रक देश मे पूंजी-निर्माण के ढांचे तथा इसकी गति को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। किसी भी देश में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन तथा पूर्ति-मांग सन्तुलन कृषि में निवेश की लाभकारिता तथा उस आय-
...

योगदान का ही एक रूप है। कृषि उत्पादन औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों तथा मजदूरी पर अपने प्रभाव द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के निवेशों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इस तरह कृषि-क्षेत्र के पूंजी निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

देश की राष्ट्रीय आय में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद कृषि में सकल पूंजी निर्माण के रूप में मापित सरकारी निवेश में हाल के वर्षों में निरन्तर गिरावट परिलक्षित हो रही है। कृषि में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के लिए एक साथ निवेश अथवा पूंजी निर्माण उतार-चढ़ाओं की ओर संकेत तकरता है।१९६०-६१ में कृषि में सकल पूंजी निर्माण १९८०-८१ की कीमतों पर१,६६८ करोड़ रू. था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा ५८९ करोड़ रू. (३५.३इ) रू. था। वर्ष १९७०-७१ में कृषि में सकल पूंजी निर्माण २,७५८ करोड़ रू. था जिसमें सरकारी क्षेत्र का हिस्सा ७८९ करोड़ रू. (२८.६इ) रहा। इस तरह १९७०-७१ में कृषि पूंजी निर्माण में सार्वजनिक निवेश का अंश १९६०-६१ की तुलना में घट गया। वर्ष १९८०-८१ में कृषि में सकल पूंजी निर्माण ४,६३६ करोड़ रू. के बराबर हुआ जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा, १,७९६ करोड़ रू. (३८.७इ) रहा। इस तरह १९७०-७१ की तुलना में १९८०-८१ में कृषि में सार्वजनिक निवेश के स्तर में कुछ सुधार हुआ। वर्ष १९८०-८१ के ही मूल्यों पर वर्ष १९९०-९१ में कृषि में सरकारी निवेश घटकर १,११४ करोड़ रू. (सकल निवेश का २९.६इ) रह गया। इस तरह इस दौरान कृषि के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त गिरावट हुई।

यद्यपि कृषि में निजी निवेश नब्बे के दशक में पर्याप्त बढ़ गया है फिर भी कृषि में सार्वजनिक निवेश
...

वर्ष १९९९-२००० में रूक गई जब सरकारी क्षेत्र का पूंजी निर्माण पिछले वर्ष में ३,८६९ करोड़ रू. के स्तर से बढ़कर ४,२२२ करोड़ रू. हो गया। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि में निवेश के हिस्से में कोई सुधार नहीं हुआ और यह १.३ प्रतिशत के स्तर पर बना रहा। वर्ष २००२-०३ के एक निर्णायक मोड़ होने की संभावना है क्योंकि कृषि में सरकारी निवेश ४,५३८ करोड़ रूपए तक पहुंच गया जो विगत ५ वर्षों की तुलना में सर्वाधिक उच्च था। यदि यह रूझान बना रहता है तो यह सरकारी क्षेत्र में कृषि की ओर अधिक संसाधनों को मोड़ने के फलस्वरूप सफलता का संकेतक होगा।

कृषि में गिरता हुआ यह सार्वजनिक निवेश चिन्ता का विषय बन हुआ है, क्योंकि यह सिंचाई, विद्युत, कृषि अनुसन्धान, सड़क, बाजार और संचार जैसे आधारभूत ढांचे के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कारण -

सार्वजनिक निवेश में कमी का कारण संसाधनों को विनिवेश से निकाल कर वर्तमान व्यय में लाना है। हाल के वर्षों में सार्वजनिक व्यय का एक बड़ा भाग परिसम्पति के सृजन के का विषय बना हुआ है। उदारीकरण के पश्चात् कृषि के सकल पूंजी निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा २१.२३ था जो घटकर १९९२-९३ में मात्र १९.७३ रह गया।

वर्ष १९९०-९१ एवं उसके बाद के वर्षों में कृषि में सकल पूंजी निर्माण की प्रवृत्ति को निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है :

भारतीय कृषि में पूंजी निर्माण (वर्ष १९९३-९४ की कीमतों पर) (करोड़ रू.)

वर्ष	योग	सरकारी	निजी	प्रतिशत हिस्सा: सरकारी	प्रतिशत हिस्सा: निजी	सकल घरेलू उत्पाद के रूप में कृषि में निवेश
१९९०-९१	१४,८३६	४,२९५	१०,६४१	२९.६	७०.४	१.९
१९९३-९४	१३,५२३	४,४६७	९,०५६	३३.०	६७.०	१.६
१९९४-९५	१४,९६९	४,९४७	१०,०२२	३३.०	६७.०	१.६
१९९५-९६	१५,६९०	४,८४९	१०,८४१	३०.९	६९.१	१.६
१९९६-९७	१६,१७६	४,६६८	११,५०८	२८.९	७१.१	१.५
१९९७-९८	१५,९४१	३,९७९	११,९६३	२५.०	७५.०	१.४
१९९८-९९	१४,८९५	३,८६९	११,०२६	२६.०	७४.०	१.३
१९९९-००	१७,३०४	४,२२२	१३,०८२	२४.४	७५.६	१.४
२०००-०१	१६,९०६	३,९२७	१२,९७९	२३.२	७६.८	१.३
२००१-०२	१७,३२८	४,१२७	१३,२०१	२३.८	७६.२	१.३
२००२-०३	१८,६५७	४,५३८	१४,११५	२४.३	७५.७	१.३

(स्रोत : आर्थिक समीक्षा, २००३-०४)

बजाय खाद्य, उर्वरक, विद्युत, सिंचाई, ऋण तथा अन्य कृषि निविष्टियों केलिए बढ़ी हुई आर्थिक सहायता के रूप में वर्तमान खर्चे में लग गया। कृषि में सार्वजनिक निवेश में हुई मन्द वृद्धि के अन्य कारण हैं- मौजूदा परियोजनाओं के अनुरक्षण पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय, सिंचाई, ग्रामीण आधारभूत ढांचा एवं अनुसन्धान को अपेक्षाकृत कम आबण्टन, खाद्य सुरक्षा पर ज्यादा बल, ग्रामीण क्षेत्रों में कारगर ऋण सहायता तथा ऋण आधारभूत ढांचे का अभाव आदि।

सुझाव -

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि में निवेश के हिस्से में सुधार लाने की दृष्टि से कृषि विकास के सम्बन्ध में कृषि की वर्तमान नीति की समीक्षा करना

उचित होगा। उर्वरकों, ग्रामीण बिजली, सिंचाई, उधार और अन्य कृषि आगतों को दी जा रही सब्सिडी को घटकार उत्पादक परिसम्पत्तियों के सृजन में प्राप्त अधिशेष को लगाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कृषि में पूंजी निर्माण को बढ़ाने की रणनीति में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए आयोजना व्यय के अनुपात को बढ़ाना, उतपदकता बढ़ाने के लिए संसाधनों का अधिक कुशल प्रयोग तथा कृषकों को अधिक निवेश के लिए अपनी बचतों का उपयोग करने में सक्षम बनाने हेतु उन्हें उपज का लाभकारी मूल्य दिलाया जाना शामिल किया जाना चाहिए। मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं एवं मृदा संरक्षण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु ऋण प्रदान करने में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामिण विकास बैंक (नाबार्ड) को कारगर भूमिका निभानी होगी। कृषि में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाना भी समोचीत होगा।

संदर्भ :

(१) Arunachalam R. Agriculture Growth and Economic Reforms Deep & Deep Publication, New Delhi.
(२) डॉ.बसुधा पुरोहित भारतीय अर्थव्यवस्था राजमुद्रा ऑफसेट चिकलठाणा, औरंगाबाद.
(३) डॉ.विजय कविमंडन, कृषी अर्थशास्त्र श्री. मंगेश प्रकाशन, नागपूर.
(४) प्रतियोगिता साहित्य, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आग्रा.

□□□

17

शेतकज्यांच्या आत्महत्या आणि शासकीय पॅकेज वरवरची मलमपट्टी

प्रा. डॉ. संतोष तु. कुटे
अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख,
कला व विज्ञान महिला महाविद्यालय,
मेहकर, ता. मेहकर, जि. बुलडाणा.

****

प्रस्तावना

आज आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६८ वर्षे झाली. पण शेतकज्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्षच झाल्याच दिसून आल्याने देशात जवळ जवळ पाच वर्षात अंसख्य बळीराजांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. आज हरितक्रांतीमुळे उत्पादन वाढले परंतु उत्पादित मालाचा झालेला खर्चही फिटू शकत नसल्याने आज ५०% पेक्षाही अधिक शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. त्यांना सावकारांकडून कर्ज घेतल्याशिवाय पर्यांच उरलेला नाही.

भारतात बँक व्यवसायाचे दोन भाग आपण करतो, एक परंपरागत व असंघटित बँक व्यवसाय आणि दुसरा संघटित बँक व्यवसाय. परंपरागत बँक व्यवसाय क्षेत्र ऐतद्देशीय बँका आणि सावकार यांचे बनले आहे. संघटित बँक व्यवसाय क्षेत्रात आधुनिक व्यापारी बँका, परकीय बँका, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया इ. चा समावेश होतो. असंघटित क्षेत्रात सावकारोचे प्राबल्य मोठ्या प्रमाणात आजही दिसून येते. बँकाकडे कर्ज मागतांना शेतकज्यांचीहोणारी हेळसांड लक्षात शेतकरी बँकाकडून कर्ज न घेता खाजगी सावकाराकडून कर्ज घेतात. आणि सावकाराच्या व व्याजाच्या विळख्यात सापडून आत्महत्येसारखे कार्य करतात. म्हणून शेतकरी आत्महत्या हा एक गंभीर आणि गहन विषय बनला आहे. सदर शोधनिबंधात महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या आणि शासनामार्फत जाहिर पॅकेज यांचा यांचा सहसंबंध अभ्यासला आहे. आणि हे पॅकेज प्रभावी न ठरता कशाप्रकारे वरवरचे प्रयोग झाले याचे विवेचन केले आहे.

शोधनिबंधाची उद्दिष्टे

१. शेतकरी आत्महत्येचे भारत आणि महाराष्ट्रासंदर्भात गांभिर्य अभ्यासणे.